

सं.ए-45011/4/2021-प्रशा.III

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक: 5<sup>th</sup> अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित फरवरी, 2021 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग को परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरुण श्याम

(अरुण श्याम चौधरी)  
उप सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: 23095091

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. अपर सचिव(एफएस एंड सीएस), आर्थिक कार्य विभाग।
14. अपर सचिव (प्रशासन एंड निवेश), आर्थिक कार्य विभाग।
15. अपर सचिव और वित्त सलाहकार (वित्त)।
16. अपर सचिव (एफएम), आर्थिक कार्य विभाग।
17. अपर सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग।
18. प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
19. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष। वरिष्ठ सलाहकार (सीएंडएसी/ एफएसएलआर/एफएस एंड सीएस)/संयुक्त सचिव (बीसी एण्ड आईईआर)/संयुक्त सचिव(निवेश)/ सलाहकार (आईईआर)/सीएए।
20. अपर महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
21. गार्ड फाइल - 2021

सं.ए-45011/4/2021-प्रशा.III

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

\*\*\*\*

विषय: फरवरी, 2021 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सार।

1. वृहद-आर्थिक विहंगावलोकन

2020-21 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए अर्थव्यवस्था धनात्मक क्षेत्र में वापस आ गई। यह वी-आकार की बहाली को मजबूत करने का एक तरीका है जिसकी शुरुआत 2020-21 की दूसरी तिमाही में हुई जो कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत सरकार द्वारा अत्यधिक कठोर लॉकडाउन लगाने के कारण पहली तिमाही में जीडीपी में बड़े जीडीपी संकुचन के कारण हुआ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी 8.0 प्रतिशत तक संकुचित होगी।

वी-आकार की बहाली निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) दोनों में पुनःप्राप्ति से आई है। लॉकडाउन को बुद्धिमत्ता से संभालने और एक सुविचारित राजकोषीय प्रोत्साहन ने मजबूत आर्थिक आधार को क्रियाकलापों का त्वरित पुनरारंभ करने की अनुमति दी है। वर्षानुवर्ष के संकुचन से पहली तिमाही में 46.4 प्रतिशत से तीसरी तिमाही में 2.6 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि से जीएफसीएफ में सुधार आया है, पहली तिमाही के 26.2 प्रतिशत के संकुचन से तीसरी तिमाही में 2.4 प्रतिशत के एक अत्यंत छोटे संकुचन से पीएफसीई ने पुनःप्राप्ति की है।

विनिर्माण में वास्तविक जीवीए में पहली तिमाही के 35.9 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में तीसरी तिमाही में 1.6 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि हुई है जबकि निर्माण में पहली तिमाही के 49.4 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में तीसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि हुई है।

अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत बना रहा क्योंकि लॉकडाउन में धीरे-धीरे रियायतें दी गईं और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन से लगातार सहायता मिलती रही जिसने अर्थव्यवस्था को सुधार के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। क्षेत्रवार वृद्धि दर अनुबंध में दी गई है।

2. अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां

2.1 (क) 01.02.2021 को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया।

(ख) इस विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के अनुदानों की पूरक मांगों के दूसरे बैच को फरवरी, 2021 के माह में संसद में प्रस्तुत किया।

2.2 (क) माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से फरवरी, 2021 के महीने के दौरान मालदीव को खेलकूद अवसंरचना में विकास के लिए 40.00 मिलियन अमरीकी डॉलर और रक्षा परियोजनाओं के लिए 50.00 मिलियन अमरीकी डॉलर राशि की ऋण सहायता दी गई।

2.3 (क) विश्व बैंक परियोजना "राज्यों (स्टार्स) के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम को मजबूत करने" हेतु 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण राशि पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) विश्व बैंक परियोजना "नागालैंड क्लास रूम शिक्षण और संसाधन सुधार परियोजना (नेक्टर)" के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से 22.02.2021 को 68.00 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण राशि पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना (चिराग) के लिए 12.2.2021 को विश्व बैंक के साथ 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए।

(घ) गुजरात त्वरित शिक्षा (जीओएएल) परिणाम पर आईबीआरडी से 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण राशि पर 11.02.2021 को हस्ताक्षर किए गए।

2.4. डॉ. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग को 23.02.2021 को एआईआईबी में भारतीय निदेशक के रूप में चुना गया है।

2.5. फरवरी 2021 महीने के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं।

(i) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस वर्ष के बजट निहितार्थ की रणनीति के बारे में मंत्रालयों/विभागों (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (लीड) मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान, आयुष और फार्मास्यूटिकल्स), विशेषज्ञों और उद्योग के सदस्यों के साथ एक वेबिनार 23.02.2021 में उपस्थिति दर्ज की।

(ii) माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने इटालियन प्रेसीडेंसी के तहत पहले जी-20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो आभासी रूप से 26.02.2021 को आयोजित किया गया था।

(iii) माननीय वित्त मंत्री ने 24.02.2021 को प्रबंध निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक आभासी बैठक की और अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण, परिवर्तनकारी और समान वसूली के लिए नीतिगत उत्तरदायित्व, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) आबंटन सहित वैश्विक स्तर पर दीर्घकालिक वित्तपोषण की आवश्यकताओं और भारत में कोविड परिस्थितियों और कमजोर देशों के लिए टीके के उत्पादन और वितरण पर चर्चा की गई।

(iv) माननीय वित्त मंत्री ने एनआईपी के कार्यान्वयन के लिए सीईओ, नीति आयोग और 22 अवसंरचना मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ 26.02.2021 को तीसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और आगे के अवसंरचना ढांचे के रोडमैप के लिए बजट के बाद के बिंदुओं पर चर्चा की।